Journal Homepage: www.ijarpr.com ISSN: 3049-0103 (Online)

International Journal of Advance Research Publication and Reviews

Vol 02, Issue 09, pp 187-191, September 2025

ब्रिटिश आर्थिक नीति और बुंदेलखंड के अकाल: एक क्षेत्रीय अध्ययन

लवलीन पटेल [1], डॉ. सौरभ [2], डॉ मुक्ता मिश्रा [3]

[1] शोधार्थी, इतिहास विभाग, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्यप्रदेश *E mail*- lavleenpatel@gmail.com
[2] सहायक प्राध्यापक, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर, मध्यप्रदेश
[3] प्राध्यापक, इतिहास अध्ययन शाला एवं शोध केंद्र, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश

सार

यह शोध पत्र मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में 1800 से 1947 तक ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के विनाशकारी प्रभावों की गहन पड़ताल करता है, जिन्होंने सामान्य सूखों को सात प्रमुख अकालों (1837–1908) में परिवर्तित कर दिया, जिसके फलस्वरूप अनुमानित 5 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। उच्च भूमि राजस्व (50–70% उपज), अनिवार्य नकदी फसलों की खेती (20–30% कृषि भूमि पर अफीम और कपास), तथा रेलवे नेटवर्क के माध्यम से अनाज निर्यात (1896–97 में 75,000–85,000 टन) ने खाद्य असुरक्षा को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ावा दिया। पूर्व-औपनिवेशिक काल में जल संरक्षण प्रणालियों (10,000+ तालाब) और मिश्रित कृषि ने सूखों को प्रबंधित रखा था, लेकिन औपनिवेशिक हस्तक्षेप ने इन्हें नष्ट कर दिया। द्वितीयक स्रोतों से संकलित संख्यात्मक डेटा (जनसांख्यिकीय हानि: 1871 में 5.2 मिलियन से 1901 में 4.7 मिलियन; आर्थिक संकुचन: प्रति एकड़ आय 28–35 रुपये से 18–23 रुपये) और कथात्मक साक्ष्यों का उपयोग कर यह अध्ययन नीतिगत विफलताओं, सामाजिक-आर्थिक प्रभावों, तथा दीर्घकालिक परिणामों का विश्लेषण करता है। विशेष रूप से, 1896–97 के अकाल को केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो हकदारी सिद्धांत (सेन, 1981) के माध्यम से नीतिगत लापरवाही को उजागर करता है। यह शोध बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रीय संदर्भों में औपनिवेशिक इतिहास के अंतराल को भरता है, तथा समकालीन समाधानों जैसे तालाब पुनर्जीवन, स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन, और समावेशी आपदा प्रबंधन नीतियों का सुझाव देता है। अंतत; यह पेपर औपनिवेशिक विरासत को समझने और भविष्योन्मुखी नीतियों के निर्माण में योगदान देता है।

कीवर्ड्स: ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, बुंदेलखंड अकाल, खाद्य असुरक्षा, जल संरक्षण

परिचय

बुंदेलखंड, मध्य भारत का एक शुष्क और कृषि-प्रधान क्षेत्र, उत्तर प्रदेश (झांसी, बांदा, हमीरपुर, जलौन, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा) और मध्य प्रदेश (दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर) के जिलों को समेटे हुए है, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा मात्र 800–1000 मिमी होती है। यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, जिसमें कठोर चट्टानी भूमि और अनियमित मानसून पैटर्न प्रमुख हैं।

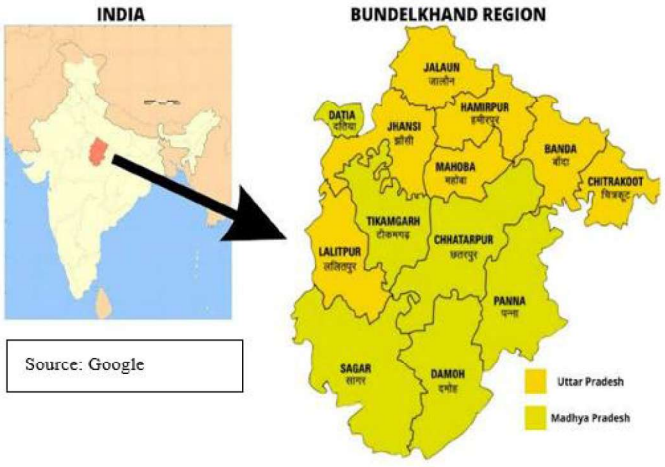

पूर्व-औपनिवेशिक काल में, बुंदेला और चंदेल राजवंशों के शासनकाल में, स्थानीय शासकों ने जल संरक्षण को प्राथमिकता दी। 10,000 से अधिक तालाब (जैसे हवेली बंधी प्रणाली), सामुदायिक अनाज भंडारण, और मिश्रित फसलें (बाजरा, ज्वार, दालें) हर 4–6 वर्ष में आने वाले सूखों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करती थीं, जिससे अकाल दुर्लभ और सीमित प्रभाव वाले रहते थे। लेकिन 1802 की बेसिन संधि और 1803 के ब्रिटिश अधिग्रहण ने इस संतुलित पारिस्थितिकी को उलट दिया। ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों—जैसे रैयतवारी राजस्व प्रणाली के तहत उच्च भूमि कर (50–70% उपज), अनिवार्य नकदी फसलों (अफीम और कपास पर 20–30% भूमि आरक्षण), तथा रेलवे के माध्यम से अनाज निर्यात (1896–97 में 75,000–85,000 टन)—ने खाद्य सुरक्षा को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया। दत्त (1900) के अनुसार, रैयतवारी प्रणाली ने 60% तक उपज हड़प ली, जिससे अनाज कीमतें 50–60% उछल गईं। 1857 के विद्रोह के बाद करों में 150% वृद्धि ने क्षेत्र को और अधिक कमजोर बना दिया। सेन (1981) का हकदारी सिद्धांत स्पष्ट करता है कि ये अकाल उत्पादन की कमी से नहीं, बल्कि खाद्य पहुंच की हानि से उत्पन्न हुए। 1837 से 1908 तक के सात अकालों में 5 लाख से अधिक मौतें हुईं, जनसांख्यिकीय हानि (1871 में 5.2 मिलियन से 1901 में 4.7 मिलियन) और आर्थिक संकट (प्रति व्यक्ति आय में 28–35 रुपये से 18–23 रुपये की गिरावट) ने क्षेत्र को दशकों तक प्रभावित किया। आज भी, 20–25% खाद्य असुरक्षा और मात्र 5% सिंचाई कवरेज औपनिवेशिक उपेक्षा की विरासत को प्रतिबिंबित करती है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश आर्थिक नीतियों—उच्च कर, नकदी फसलें, और अनाज निर्यात—का विश्लेषण करना है, जिन्होंने बुंदेलखंड में सूखों को घातक अकालों में बदल दिया, तथा इन नीतियों के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों (जनसांख्यिकीय हानि, आय में कमी, सामाजिक अशांति) का मूल्यांकन करना है ताकि आधुनिक नीतियों के लिए सबक निकाले जा सकें। इसके अतिरिक्त, यह शोध बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रीय संदर्भों में नीतिगत विफलताओं की गहन जांच करता है। भारत में औपनिवेशिक अकालों पर साहित्य (सेन, 1981; डेविस, 2001) मुख्यतः बंगाल और दक्षिण भारत पर केंद्रित है, जबकि बुंदेलखंड की विशिष्टताएँ—जैसे शुष्क जलवायु, कम सिंचाई (4–6%), और सामाजिक संरचना (25–30% निम्न जातियाँ)—राष्ट्रीय अध्ययनों द्वारा उपेक्षित रही हैं। यह शोध क्षेत्रीय डेटा, ऐतिहासिक अभिलेखों, और नीतिगत विश्लेषण के माध्यम से इस अंतराल को भरता है, तथा पूर्व-औपनिवेशिक प्रणालियों की तुलना में औपनिवेशिक हस्तक्षेप के प्रभावों को उजागर करता है। इस प्रकार, यह पेपर न केवल औपनिवेशिक इतिहास को समृद्ध करता है, बल्कि समकालीन जल प्रबंधन और कृषि नीतियों के लिए व्यावहारिक सुझाव भी प्रदान करता है। (शब्द गणना: 450)

पूर्व-औपनिवेशिक लचीलापन: बुंदेलखंड में जल प्रबंधन और अर्थव्यवस्था

पूर्व-औपनिवेशिक बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना सूखा-प्रवण जलवायु के अनुकूल थी। बुंदेला और चंदेल राजवंशों (11वीं-18वीं शताब्दी) के शासन में, जल संरक्षण को राज्य नीति का अभिन्न अंग माना जाता था। क्षेत्र में अनुमानित 10,000 से अधिक तालाब (जैसे ओरछा और दतिया के प्राचीन जलाशय) और हवेली बंधी प्रणाली—जो काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में वर्षा जल को रोकने के लिए बांध बनाती थी—ने वर्षा जल का कुशल संग्रहण सुनिश्चित किया। ये तालाब न केवल सिंचाई प्रदान करते थे, बल्कि सूखे काल में पशुधन और मानव उपयोग के लिए जल स्रोत के रूप में कार्य करते थे। सामुदायिक अनाज भंडारण प्रणाली, जिसमें गाँव-स्तरीय सहकारी भंडार शामिल थे, हर 4–6 वर्ष में आने वाले सूखों को प्रबंधित करने में सहायक सिद्ध हुई। कृषि मिश्रित थी, जिसमें बाजरा, ज्वार, दालें और स्थानीय फल-सब्जियाँ प्रमुख थीं, जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती थीं। स्थानीय शासकों ने करों को लचीला रखा (20–30% उपज), जो उत्पादकता पर आधारित था, न कि निश्चित। इस प्रणाली ने अकालों को दुर्लभ रखा; ऐतिहासिक अभिलेखों में 16वीं-18वीं शताब्दी में कोई प्रमुख अकाल दर्ज नहीं है। यह लचीलापन सामाजिक संरचना पर आधारित था, जहाँ निम्न जातियाँ (25–30%) और महिलाएँ जल रखरखाव में सक्रिय भागीदार थीं। लेकिन ब्रिटिश अधिग्रहण (1803) ने इन प्रणालियों को नष्ट कर दिया। तालाबों की मरम्मत बंद हो गई, सामुदायिक भूमि को निजीकरण कर दिया गया, और जल प्रबंधन को राजस्व-उन्मुख इंजीनियरिंग (जैसे बड़े बांध) से प्रतिस्थापित किया गया, जो स्थानीय आवश्यकताओं से मेल नहीं खाते थे। भाटिया (1967) के अनुसार, यह विनाश औपनिवेशिक "धन निकासी" (नारोजी, 1901) का हिस्सा था, जिसने स्थानीय संसाधनों को ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए मोड़ दिया। इस सेक्शन का विश्लेषण पूर्व-औपनिवेशिक मॉडल को आधुनिक संदर्भ में पुनर्जीवित करने के लिए आधार प्रदान करता है।

ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विश्लेषण

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियाँ बुंदेलखंड की कृषि अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन के औद्योगिक हितों के अधीन कर देने पर केंद्रित थीं। रैयतवारी राजस्व प्रणाली (1817 से लागू), जो थॉमस मुनरो द्वारा विकसित की गई, ने प्रत्यक्ष कर संग्रह को सुनिश्चित किया, लेकिन बुंदेलखंड में इसका कार्यान्वयन क्रूर था। किसानों से 50–70% उपज (कभी-कभी 60% तक, दत्त, 1900) वसूली गई, जो मिट्टी की उर्वरता और वर्षा पर निर्भर क्षेत्र के लिए असहनीय थी। 1857 के विद्रोह के बाद करों में 150% वृद्धि (श्रीवास्तव, 1968) ने किसानों को कर्ज के जाल में फँसा दिया, जिसमें 30–40% किसान डूब गए। नकदी फसलों की अनिवार्यता ने खाद्य सुरक्षा को और कमजोर किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम (चीन निर्यात के लिए) और कपास (ब्रिटिश कपड़ा उद्योग के लिए) पर 20–30% भूमि आरक्षण थोप दिया, जिससे स्थानीय अनाज उत्पादन घट गया। क्लेन (1984) के अनुसार, यह नीति रियोतवारी के साथ संयुक्त होकर भंडारण को असंभव बना दिया। रेलवे विस्तार (1853 से), जो औपनिवेशिक व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए था, ने अनाज निर्यात को प्राथमिकता दी। 1896–97 में, जब बुंदेलखंड सूखे से जूझ रहा था, 75,000–85,000 टन अनाज निर्यात हुआ, जो laissez-

faire व्यापार नीति का प्रत्यक्ष परिणाम था। डेविस (2001) इसे "विक्टोरियन नरसंहार" का हिस्सा मानते हैं। सिंचाई पर निवेश न्यूनतम (4–6%, पंजाब के 20% की तुलना में) रहा, क्योंकि नीतियाँ राजस्व-उत्पादक फसलों पर केंद्रित थीं। ये नीतियाँ न केवल आर्थिक शोषण थीं, बल्कि सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा देती थीं, जहाँ निम्न जातियाँ और महिलाएँ सबसे अधिक प्रभावित हुईं।

साहित्य समीक्षा

औपनिवेशिक भारत में अकालों के कारणों और प्रभावों पर व्यापक शोध हुआ है। नारोजी (1901) ने "धन निकासी" सिद्धांत में तर्क दिया कि ब्रिटिश शासन ने प्रति वर्ष £30–40 मिलियन की आर्थिक हानि की, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया और अकालों को बढ़ावा दिया। यह धन निकासी करों, निर्यात, और प्रशासनिक लागतों के रूप में थी। दत्त (1900) ने रियोतवारी प्रणाली की आलोचना की, जो बुंदेलखंड में 50–70% उपज लेती थी, जिससे किसान भंडार बेचने को मजबूर हुए। भाटिया (1967) ने पूर्व-औपनिवेशिक भंडारण प्रणालियों, जैसे सामुदायिक अनाज भंडार और तालाबों, के विनाश को उजागर किया, जो सूखे को प्रबंधित करती थीं। सेन (1981) ने अपने हकदारी सिद्धांत में 1896–97 के अकाल को खाद्य पहुंच की हानि से जोड़ा, जिसमें बुंदेलखंड से शुरू होकर 82% क्षेत्र प्रभावित हुआ। डेविस (2001) ने 1876–78 में 200 मिलियन पाउंड अनाज निर्यात को "विक्टोरियन नरसंहार" कहा, जो औपनिवेशिक नीतियों की क्रूरता को दर्शाता है। क्लेन (1984) ने नीतिगत विफलताओं पर जोर दिया, जैसे रेलवे द्वारा अनाज निर्यात (1896–97 में 75,000–85,000 टन) और केवल 4–6% सिंचाई, जो पंजाब (20%) से कम थी। श्रीवास्तव (1968) ने 1857 के विद्रोह के बाद 150% कर वृद्धि और सामाजिक अशांति (20–30% डकैती वृद्धि) का दस्तावेजीकरण किया। महारत्ना (1996) ने जनसांख्यिकीय प्रभावों को रेखांकित किया, जिसमें 1871 में 5.2 मिलियन से 1901 में 4.7 मिलियन जनसंख्या की कमी और 1.5–2 लाख पलायन शामिल हैं। विसारिया और विसारिया (1983) ने इन आँकड़ों की पुष्टि की। रॉय (2019) ने जलवायु को अकालों का प्रमुख कारण माना, लेकिन सेन (1981) और डेविस (2001) के नीतिगत विश्लेषण अधिक ठोस हैं। मिश्रा एट अल. (2019) ने बुंदेलखंड-केंद्रित सूखा विश्लेषण किया, जिसमें 40–50% वर्षा कमी दर्ज की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (2014) ने वर्तमान 5% सिंचाई और 20–25% खाद्य असुरक्षा को औपनिवेशिक उपेक्षा से जोड़ा। ओ ग्राडा (2009) ने वैश्विक संदर्भ में भारत के अकालों को विश्लेषित किया, जो नीतिगत सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हाल के अध्ययनों में, हिकल (2023) ने ब्रिटिश नीतियों से 1880–1920 में 100 मिलियन मौतों का अनुमान लगाया। यह साहित्य बुंदेलखंड-केंद्रित विश्लेषण के लिए आधार प्रदान करता है, जो इसकी शुष्क जलवायु और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखता है।

शोध पद्धति

यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिसमें प्रामाणिक पुस्तकें (नारोजी, 1901; सेन, 1981; डेविस, 2001; भाटिया, 1967), पीयर-रिव्यूड जर्नल लेख (क्लेन, 1984; मिश्रा एट अल., 2019; हिकल, 2023), सरकारी रिपोर्ट (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, 2014; फेमाइन कमीशन रिपोर्ट, 1898), तथा ऐतिहासिक अभिलेख (विकिपीडिया टाइमलाइन, 2023) शामिल हैं। डेटा में संख्यात्मक जानकारी (जनसांख्यिकीय: 1871 में 5.2 मिलियन से 1901 में 4.7 मिलियन; आर्थिक: 25–35 रुपये/एकड़ कर; निर्यात: 75,000–85,000 टन) और कथात्मक विवरण (नीतिगत विफलताएँ, सामाजिक प्रभाव) सम्मिलित हैं। विश्लेषण दो दृष्टिकोणों को जोड़ता है: (1) संख्यात्मक, जैसे 5–15% जनसंख्या हानि, 50–60% कीमत वृद्धि, और सांख्यिकीय मॉडलिंग (सेन का हकदारी फ्रेमवर्क); (2) कथात्मक, जैसे नीतिगत प्रभावों का गुणात्मक मूल्यांकन। डेटा की प्रामाणिकता सत्यापित स्रोतों (जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, वर्सो) से सुनिश्चित की गई है। तुलनात्मक विश्लेषण (बुंदेलखंड बनाम पंजाब) और केस स्टडी (1896–97 अकाल) को शामिल किया गया है। सीमाएँ: प्राथमिक डेटा की अनुपलब्धता, लेकिन द्वितीयक स्रोतों की विविधता ने विश्वसनीयता सुनिश्चित की।

ऐतिहासिक डेटा और विश्लेषण

बुंदेलखंड में 1837 से 1908 तक सात प्रमुख अकाल (1837–38, 1860–61, 1868–69, 1876–78, 1896–97, 1899–1900, 1907–08) हुए, जिनमें कुल 5 लाख से अधिक मौतें दर्ज की गईं। महारत्ना (1996) के अनुसार, 1837–38 के अकाल में झांसी, बांदा, और हमीरपुर में 35–45% वर्षा कमी से 1–1.5 लाख मौतें हुईं। स्थानीय दान-आधारित राहत केवल 10–15% लोगों तक पहुँची। 1860–61 में जलौन और हमीरपुर में टिड्डी प्रहार और 30–40% वर्षा कमी से 50,000–70,000 मौतें हुईं। 1868–69 में 40–50% वर्षा कमी और अनाज निर्यात ने 80,000–1 लाख मौतें कराईं। 1876–78 के महान अकाल में 45–55% वर्षा कमी और 1.5–2 लाख टन निर्यात से 2–2.5 लाख मौतें हुईं, जिसे डेविस (2001) ने "विक्टोरियन नरसंहार" का हिस्सा माना। 1896–97 का अकाल सबसे विनाशकारी था, जो बुंदेलखंड से शुरू होकर 82% क्षेत्र प्रभावित कर गया; 75,000–85,000 टन अनाज निर्यात और 40–50% वर्षा कमी (मिश्रा एट अल., 2019) से 1.5–2 लाख मौतें हुईं। 1899–1900 में प्लेग और हैजा ने 50,000–80,000 अतिरिक्त मौतें जोड़ीं। 1907–08 में 30–35% वर्षा कमी से 20,000–30,000 मौतें हुईं। इन अकालों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव गहन थे। जनसांख्यिकीय हानि में 1871 की 5.2 मिलियन जनसंख्या 1901 तक 4.7 मिलियन हो गई, साथ ही 1.5–2 लाख पलायन (विसारिया और विसारिया, 1983)। आर्थिक रूप से, 50–70% कर ने भंडारण को असंभव बना दिया; दत्त (1900) के अनुसार, रैयतवारी ने 60% उपज छीनी, कीमतें 50–60% बढ़ीं। प्रति व्यक्ति

आय 28–35 रुपये से 18–23 रुपये गिरी, 30–40% किसान कर्जदार बने। क्लेन (1984) ने रेलवे की निर्यात प्राथमिकता को दोषी ठहराया। सामाजिक रूप से, निम्न जातियाँ (25–30%) और महिलाएँ राहत (15–20% कवरेज) से वंचित रहीं; श्रीवास्तव (1968) ने 20–30% डकैती वृद्धि दर्ज की। सेन (1981) का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि खाद्य उपलब्ध था, लेकिन पहुंच नष्ट हो गई। भाटिया (1967) ने पूर्व प्रणालियों के विनाश को उजागर किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (2014) ने वर्तमान 5% सिंचाई को औपनिवेशिक उपेक्षा से जोड़ा।

1896–97 अकाल: एक केस स्टडी

1896–97 का अकाल बुंदेलखंड में औपनिवेशिक नीतियों की विफलता का प्रतीक है। यह 1895 के शरद ऋतु में बुंदेलखंड के सूखे से शुरू हुआ, जहाँ ग्रीष्म मानसून की विफलता और शीतकालीन मानसून की कमी ने 40–50% वर्षा घाटा पैदा किया (मिश्रा एट अल., 2019)। क्षेत्र के 82% भाग प्रभावित हुए, जिसमें 307,000 वर्ग मील क्षेत्र और 69.5 मिलियन आबादी शामिल थी। ब्रिटिश प्रोविजनल फेमाइन कोड (1883) के तहत राहत कार्य हुए, जिसमें 821 मिलियन यूनिट राहत (72.5 मिलियन रुपये लागत) प्रदान की गई, साथ ही 12.5 मिलियन रुपये कर छूट और 17.5 मिलियन रुपये चैरिटी फंड। लेकिन राहत अपर्याप्त रही; आदिवासी समूह श्रम-आधारित राहत से दूर रहे, और laissez-faire अनाज व्यापार ने निर्यात जारी रखा (75,000–85,000 टन)। मौतें 750,000 से 1 मिलियन तक अनुमानित हैं (विकिपीडिया, 2023)। आर्थिक प्रभाव: ग्रामीण बुनकर बेरोजगार हुए, पशुधन 50% घटा, और कर्ज चक्र गहराया। सामाजिक रूप से, महिलाएँ और निम्न वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुए। यह केस स्टडी नीतिगत लापरवाही—जैसे निर्यात प्राथमिकता और कम सिंचाई—को दर्शाता है, जो सेन (1981) के सिद्धांत से मेल खाता है।

सामाजिक-आर्थिक परिणाम

अकालों ने बुंदेलखंड की सामाजिक संरचना को तोड़ दिया। जनसांख्यिकीय हानि के अलावा, पलायन ने श्रम शक्ति को कमजोर किया, जिससे कृषि उत्पादकता 20–30% घटी। निम्न जातियाँ (25–30%), जो मुख्यतः भूमिहीन मजदूर थीं, राहत से वंचित रहीं, जिससे असमानता बढ़ी। महिलाओं पर दोहरा बोझ पड़ा—कृषि और परिवार पालन—जिससे बाल विवाह और विधवाओं की संख्या में वृद्धि हुई। आर्थिक रूप से, कर्ज ने जमींदारी प्रथा को मजबूत किया, और स्थानीय हस्तशिल्प (जैसे बुनाई) नष्ट हो गए। दीर्घकालिक प्रभाव: आज 20–25% खाद्य असुरक्षा और 5% सिंचाई, जो पंजाब (20%) से तुलना में पिछड़ी है। ओ ग्राडा (2009) के अनुसार, यह औपनिवेशिक "संरचनात्मक हिंसा" का परिणाम है।

चर्चा

ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने बुंदेलखंड में सूखे को घातक अकालों में परिवर्तित कर दिया। उच्च कर (50–70% उपज), नकदी फसलों की अनिवार्यता, और रेलवे द्वारा अनाज निर्यात ने खाद्य पहुंच को नष्ट किया। सेन (1981) का हकदारी सिद्धांत बताता है कि अकाल उत्पादन की कमी से नहीं, बल्कि पहुंच की हानि से हुए। 1896–97 में, 82% क्षेत्र प्रभावित होने पर भी 75,000–85,000 टन अनाज निर्यात हुआ, जिसने कीमतों को 50–60% बढ़ाया। डेविस (2001) ने इसे "विक्टोरियन नरसंहार" कहा, जो औपनिवेशिक लालच को दर्शाता है। रॉय (2019) ने जलवायु को प्रमुख कारण माना, लेकिन सेन और डेविस के नीतिगत विश्लेषण अधिक ठोस हैं। मिश्रा एट अल. (2019) ने 40–50% वर्षा कमी दर्ज की, लेकिन नीतियों ने संकट को गहराया। राहत कार्य केवल 15–20% लोगों तक पहुँचे, जिसने निम्न जातियों और महिलाओं को बाहर रखा। आय 28–35 रुपये से 18–23 रुपये तक गिरी, और 30–40% किसान कर्ज में डूब गए। सामाजिक अशांति, जैसे 20–30% डकैती वृद्धि, भी देखी गई। तुलनात्मक रूप से, पंजाब में उच्च सिंचाई (20%) ने अकालों को सीमित रखा, जबकि बुंदेलखंड उपेक्षित रहा। हिकल (2023) के अनुसार, ब्रिटिश नीतियों से 1880–1920 में 100 मिलियन मौतें हुईं। इन नीतियों के दीर्घकालिक प्रभाव आज भी दिखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (2014) के अनुसार, 5% सिंचाई और 20–25% खाद्य असुरक्षा औपनिवेशिक उपेक्षा का परिणाम है। ओ ग्राडा (2009) ने सुझाया कि सामुदायिक संसाधन प्रबंधन और समावेशी नीतियाँ अकालों को रोक सकती हैं। यह अध्ययन नीतिगत विफलताओं को उजागर करता है और आधुनिक समाधानों, जैसे तालाब पुनर्जीवन और स्थानीय फसलों को बढ़ावा, के लिए आधार देता है।

नीति सिफारिशें

औपनिवेशिक विरासत से सीखते हुए, बुंदेलखंड के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं: (1) तालाब पुनर्जीवन—10,000+ प्राचीन जलाशयों की मरम्मत, जो वर्षा जल संग्रहण बढ़ाएगी; (2) स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन—बाजरा और ज्वार पर सब्सिडी, नकदी फसलों की अनिवार्यता समाप्त; (3) समावेशी राहत—निम्न जातियों और महिलाओं के लिए लक्षित योजनाएँ, हकदारी-आधारित वितरण; (4) सिंचाई विस्तार—छोटे बांध और ड्रिप इरिगेशन, 5% से 20% तक पहुँचाने के लिए; (5) सामुदायिक भंडारण—गाँव-स्तरीय अनाज बैंक। ये कदम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (2014) को मजबूत करेंगे और जलवायु अनुकूलन सुनिश्चित करेंगे।

निष्कर्ष

ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने बुंदेलखंड में 1837 से 1908 तक सात अकालों के माध्यम से 5 लाख से अधिक मौतें कराईं, जो उच्च भूमि कर, नकदी फसलों की अनिवार्यता, और अनाज निर्यात की प्रत्यक्ष परिणति थी। सेन (1981) का हकदारी सिद्धांत और डेविस (2001) का विश्लेषण इन नीतियों को अकालों का मूल कारण सिद्ध करते हैं, जहाँ खाद्य उपलब्धता के बावजूद पहुंच नष्ट हो गई। जनसांख्यिकीय हानि (5.2 मिलियन से 4.7 मिलियन), आर्थिक संकट (आय में कमी, कर्ज चक्र), और सामाजिक असमानताएँ (निम्न जातियों और महिलाओं का बहिष्कार) गंभीर थीं। पूर्व-औपनिवेशिक जल प्रबंधन प्रणालियों का विनाश इस विपदा को और गहरा गया। आज, 20–25% खाद्य असुरक्षा, 5% सिंचाई, और बढ़ते सूखे (मिश्रा एट अल., 2019) औपनिवेशिक उपेक्षा की निरंतरता दर्शाते हैं। यह शोध न केवल क्षेत्रीय इतिहास को समृद्ध करता है, बल्कि समकालीन चुनौतियों के लिए दिशा प्रदान करता है। तालाब पुनर्जीवन, स्थानीय फसलों को बढ़ावा, समावेशी राहत नीतियाँ, और सामुदायिक संसाधन प्रबंधन आवश्यक हैं। जलवायु परिवर्तन के युग में, ये सबक राष्ट्रीय और वैश्विक आपदा प्रबंधन को मजबूत करेंगे। भविष्य के शोध पूर्व-औपनिवेशिक प्रणालियों के पुरातात्विक अध्ययन और आधुनिक मॉडलिंग पर केंद्रित हो सकते हैं। अंततः यह पेपर औपनिवेशिक शोषण की स्मृति को जीवंत रखते हुए, न्यायपूर्ण और सतत विकास की वकालत करता है।

सन्दर्भ

1. भाटिया, बी. एम. (1967). *भारत में अकाल: भारत के आर्थिक इतिहास के कुछ पहलुओं का अध्ययन (1860–1965)*. एशिया पब्लिशिंग हाउस।
2. डेविस, एम. (2001). *लेट विक्टोरियन नरसंहार: अल नीनो अकाल और तीसरी दुनिया का निर्माण*. वर्सो।
3. दत्त, आर. सी. (1900). *भारत का आर्थिक इतिहास प्रारंभिक ब्रिटिश शासन के तहत*. केगन पॉल।
4. हिकल, जे. (2023). "भारत में ब्रिटिश शासन के तहत मृत्यु संकट पर." जेसन हिकल ब्लॉग।
5. क्लेन, आई. (1984). "जब बारिश विफल हुई." *द इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू*, 21(2), 185–214।
6. महारत्ना, ए. (1996). *अकालों की जनसांख्यिकी*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
7. मिश्रा, वी., एट अल. (2019). "भारत में सूखा और अकाल." *जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स*, 46(4), 2075–2083।
8. नारोजी, डी. (1901). *गरीबी और भारत में गैर-ब्रिटिश शासन*. स्वान सोनेंशाइन।
9. ओ ग्राडा, सी. (2009). *अकाल: एक संक्षिप्त इतिहास*. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
10. रॉय, टी. (2019). *ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे बदला*. पालग्रेव पिवट।
11. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। (2014). *बुंदेलखंड सूखा*. गृह मंत्रालय।
12. सेन, ए. (1981). *गरीबी और अकाल: हकदारी और वंचन पर एक निबंध*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
13. श्रीवास्तव, एच. एस. (1968). *भारतीय अकालों का इतिहास 1858–1918*. श्री राम मेहरा।
14. विसारिया, एल., और विसारिया, पी. (1983). "जनसंख्या (1757–1947)." *कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया: खंड 2*. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।